



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
अपील संख्या - 3/25

GCMS NO 2025/7

1. सुशीला पुत्री मनोहरलाल पत्नि भगवान सिंह जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
2. सन्तरा पुत्री मनोहरलाल पत्नि अमृतलाल जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
3. सुगरो पुत्री मनोहर लाल पत्नि नेहरू जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
4. भूरवाई पुत्री मनोहरलाल पत्नि वीरसिंह जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
5. गीतादेवी पुत्री मनोहर लाल पत्नि रामगोपाल जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
6. भीरा देवी पुत्री मनोहरलाल पत्नि बाबू जाति जाटव निवासी बाढ मिल्कीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी

अपीलांत

बनाम

1. रामसिंह पुत्र हरि
2. लक्ष्मण पुत्र हरि
3. ममता पुत्री हरि
4. रामेश्वर पुत्र सुगन्या जातियान गुर्जर निवासीयान सालौदा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
5. रामनिवास पुत्र अमृतलाल
6. सुनिता पत्नि धनसिंह जातियान भीना निवासीयान पीलोदा तहसील वजीरपुर
7. भूमिका देवी उर्फ भूदेई बेवा ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
8. सायल पुत्र ओमप्रकाश
9. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश दोनो नाबालिंग जरिये संरक्षक माता भूमिका देवी उर्फ भूदेई बेवा ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर
10. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पोंड

(अपील विरुद्ध मु०नं० 160/12 निर्णय दिनांक 1.4.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला० श्री तरुण शर्मा

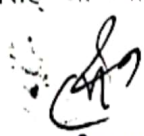
अभिभाषक रैस्पोंड संख्या 7 ता 9 की और से श्री संतोष कुमार जाटव

दिनांक 10.9.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 1.4.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रामनिवास पत्नि अमृतलाल व सुनिता पत्नि धर्म सिंह जातियान भीना निवासीयान पीलोदा द्वारा एक प्रार्थना पत्र


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

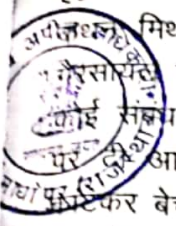


अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोंड संख्या 1, 2, 3 के पिता हरि व रेस्पोंड संख्या 4 रामेश्वर के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की भूमि हाल ख०न० 282 रकबा 0.60 है० ग्राम सालोदा में स्थित है। जिसका मौके पर पक्षकारा ने विभाजन कर रखा है। सायलान ने अपने हिस्से की भूमि को स्टाम्पो के जरिये प्लाटो के रूप में बेचान कर दिया है। गैरसायलान के हिस्से की भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। जिस पर सायलान का कब्जा चला आ रहा है। गैरसायलान की नियत अब खराब है। अब वे अपने हिस्से की भूमि को प्लाटो के रूप में विक्रय करने के बाद अब सायलान के हिस्से की भूमि को भी प्लाटो के रूप में दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम सालोदा में स्थित भूमि हाल खसरा न० 282 रकबा 0.60 है० को बिना विभाजन के न तो स्वयं कोई निर्माण करे तथा ना ही किसी अन्य से करावे तथा ना ही भूमि की किस्म को परिवर्तित करे। विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ सायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया गया कि भूमि खसरा न० 282 रकबा 0.60 है० की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। जिससे व्यथित होकर अपीलांतगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सिद्धान्तों व मिसल के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत क पिता जो कि वादग्रस्त जायदाद के रिकार्डेड खातेदार रहे हैं को पाबंद किये जाने में भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का रहा है अन्य पक्षकार भी विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार रहे हैं। किन्तु उसके बाबजूद भी उक्त आदेश जारी करने में भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तीन सिद्धान्त प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु का बिना विधिक विवेचन किये उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना विधिक विवेचन किये आनन फानन में बिना विधिक प्रावधानों की विवेचना कर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मात्र आर्डरशीट पर सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो कि आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैरसायल हरि की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान को रेस्पोंड संख्या 1 ता 3 पक्षकार बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की बजह से मृत पक्षकारों के वारिसान के नाम नामा० की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इस प्रकार मृत व्यक्तियों के वारिसान के नाम नामा० खोले जाने के आदेश पारित करते हुए अतः अपीलांत की अपील स्वीकार करमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि भूमि खसरा न0 280 रकबा 0.60 है0 ग्राम सालोदा जो गैरसायल 1 लगायत 2 की पैतृक एवं स्वामित्व मे रही है। अपीलांट का यह मिथ्या है कि भूमि खाली पडी हुई है जबकि सत्यता यह है कि उक्त आराजीयात मे संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से मे मकान बना रखे है। उक्त खाली भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। सायलान/अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार आई प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त भूमि को पूर्व मे ही जरिये स्टाम्प प्लाट फोर बेचान किया जा चुका है तथा विभिन्न लोगो ने मकान बना लिये है। अपीलांट/सायलान द्वारा रेस्पो/गैरसायलान को हेरान परेशान करने की बजह से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण ही विधिवत रूप से उभयपक्ष को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामने आये है कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात दर्ज है। इस तथ्य को सायल एवं गैरसायल द्वारा स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता के कानूनी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे मृत व्यक्तियों के वारिसान के नाम नामा0 खुलने की प्रकिया नहीं हो पा रही है। चूकि: उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। नामा0 प्रकिया एक सतत प्रकिया है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड मे लंबित किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अतः न्यायहित मे मृतको के विधिक वारिसानो के नाम अन्तरण रोके जाने की हद तक पारित आदेश निरस्त करते हुए शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 160/12 मे पारित निर्णय दिनांक 1.4.15 मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा न0 282 रकबा 0.60 है0 ग्राम सालोदा के संयुक्त खातेदारो मे से यदि कोई पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.4.15 के पश्चात फौत हुआ हो तो उसके विधिक वारिसान के नाम नामा0 संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। शेष निर्णय अधिनस्थ न्यायालय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नोट:- निर्णय के अंतिम बीसरी लाइन मे अंकित "दिनांक 1/4/15 के अन्तर्गत पर संजालीआई पालि मनोहर लाल 461 जावे।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर